

BSNL EMPLOYEES UNION (CHQ) NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES-BSNL

नई दिल्ली-110008

दिनांक: 02-02-2026

12-02-2026 को देशव्यापी आम हड़ताल सामूहिक रूप से जुड़ें और अभूतपूर्व सफल बनायें

प्रिय साथियों,

सेंट्रल ट्रेड यूनियनों और इंडिपेंडेंट फेडरेशन और यूनियनों के जॉइंट प्लेटफॉर्म ने 9 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में वर्कर्स का नेशनल कन्वेंशन ऑर्गनाइज़ किया। BSNLEU और NFTE BSNL ने इस कन्वेंशन में हिस्सा लिया। इस कन्वेंशन में 12 फरवरी 2026 को जनरल स्ट्राइक ऑर्गनाइज़ करने का आह्वान किया गया। वर्कर्स के नेशनल कन्वेंशन के पार्टिसिपेंट होने के नाते, BSNLEU और NFTE BSNL ने एम्प्लॉइज से इस जनरल स्ट्राइक में हिस्सा लेने का आह्वान किया है।

सरकार ने मज़दूर-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक चार लेबर कोड और श्रम शक्ति नीति-2025 लागू कर दी है। चारों लेबर कोड के लागू होने से ट्रेड यूनियन मूवमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। एसोसिएशन बनाने का अधिकार, कलेक्टिव बारगेनिंग का अधिकार और हड़ताल करने के अधिकार पर सख्त शर्तें लगाई जाएंगी। इसके अलावा, लगभग 70% फैक्ट्रियों/संस्थाओं और 90% ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर के मज़दूरों को लेबर लॉ के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। इन सब से मज़दूर आज के ज़माने के गुलाम बन जाएंगे।

केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर विरोधी नीतियां लागू कर रही है। सरकार किसी न किसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोयला, स्टील, तेल वगैरह सेक्टर में पब्लिक सेक्टर कंपनियों को कमज़ोर कर रही है, जिसका आखिरी मकसद उन्हें प्राइवेट करना है। बीएसएनएल इसी पॉलिसी का शिकार है। इस भेदभाव वाली पॉलिसी की वजह से बीएसएनएल 4G और 5G सर्विस में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से पीछे है। इससे बीएसएनएल के फाइनेंशियल रिवाइवल पर बुरा असर पड़ रहा है। बीएसएनएल के लिए पहला रिवाइवल पैकेज लागू हुए 5 साल हो चुके हैं। लेकिन, बीएसएनएल अभी भी फाइनेंशियल संकट में है। यह सरकार की बीएसएनएल विरोधी और प्राइवेट के हक में नीतियों का नतीजा है। हम मांग करते हैं कि बीएसएनएल को अच्छी क्वालिटी की 4G और 5G सर्विस जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। यह बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए एक कदम होगा।

बीएसएनएल 2009-10 से घाटे में चल रहा है, इसका कारण बताते हुए बीएसएनएल कर्मचारियों को 01-01-2017 से उनके वेज रिविज़न से मना कर दिया गया है। बीएसएनएल में यूनियनों और एसोसिएशनों के एकजुट संघर्षों के कारण, मान्यता प्राप्त यूनियनों और बीएसएनएल मैनेजमेंट के बीच 08-10-2025 को वेज रिविज़न एग्रीमेंट पर साइन किए गए हैं। हालांकि, यह वेज रिविज़न एग्रीमेंट तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक केंद्रीय कैबिनेट बीएसएनएल को तीसरे पे रिविज़न कमेटी के "अफोर्डेबिलिटी क्लॉज़" से छूट नहीं देती। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज़ में ढील देना और वेज रिविज़न को लागू करना 12 फरवरी 2026 को होने वाली इस आम हड़ताल की एक अहम मांग है।

"मैनपावर के रीस्ट्रक्चरिंग" के नाम पर सभी कैडर में पोस्ट बड़े पैमाने पर खत्म कर दी गई हैं। इससे नॉन-एग्जीक्यूटिव के प्रमोशन की संभावनाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा, एग्जीक्यूटिव और नॉन-

एग्जीक्यूटिव के बीच प्रमोशनल पॉलिसी में गंभीर भेदभाव है। बीएसएनएल के काम बड़े पैमाने पर आउटसोर्स किए जा रहे हैं। इससे कर्मचारी बेकार हो रहे हैं। इन सभी मुद्दों को सरकार और बीएसएनएल मैनेजमेंट को ठीक से सुलझाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की छंटनी बंद होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल वर्कर के लिए मिनिमम वेज, EPF और ESI पक्का किया जाना चाहिए।

ऊपर बताई गई मांगों को पूरा करने के लिए, BSNLEU और NFTE BSNL, बीएसएनएल कर्मचारियों से 12 फरवरी 2026 को होने वाली आम हड़ताल में बड़े पैमाने पर शामिल होने और बीएसएनएल में आम हड़ताल को सफल बनाने की अपील करते हैं।

मांगों का चार्टर :

भाग - A

- श्रम शक्ति नीति-2025 और मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं और नियमों को रद्द किया जाए।
- पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और सरकारी सेवाओं का प्राइवेटाइजेशन बंद करो।
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) को खत्म किया जाएगा।
- पीएसयू में ऑपरेशन और मेंटेनेंस की आउटसोर्सिंग बंद करें।
- फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट और अलग-अलग स्कीम और बहाने से अप्रेंटिस, ट्रेनी वगैरह को काम पर रखना बंद करें।
- परमानेंट और पक्की नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रखना बंद करें।
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों, ठेका कामगारों और योजना कामगारों सहित सभी कामगारों के लिए 26,000 रुपये प्रति माह का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए।

भाग - B

- 'अफोर्डेबिलिटी क्लॉज' में तुरंत ढील दी जाए और बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन का जल्द से जल्द सेटलमेंट सुनिश्चित किया जाए।
- बीएसएनएल को कमजोर न करें। तुरंत अच्छी क्वालिटी की 4G सर्विस और 5G सर्विस को तेज़ी से शुरू करना पक्का करें।
- नॉन-एग्जीक्यूटिव के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी लागू करें। नॉन-एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव के प्रमोशन के तरीकों में भेदभाव खत्म करें।
- मैनपावर की रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर और बेईमानी से पदों को खत्म करने का काम वापस लिया जाए। सभी नॉन-एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए इंटरनल एग्जाम में काफी वैकेंसी पक्की की जाए।
- बीएसएनएल के कामों की बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग तुरंत बंद हो। सभी कैडर में खाली पोस्ट भरी जाएं।
- बीएसएनएल में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की छंटनी बंद हो और रोज़ाना के ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस से टीआईपी को हटाया जाए।
- कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का शोषण बंद करें। 2025 तक मिनिमम वेज, ईपीएफ और ईएसआई और डीए का बकाया पक्का करें।



(अनिमेष चंद्र मित्रा)

महासचिव, BSNLEU



(चंद्रेश्वर सिंह)

महासचिव, एनएफटीई बीएसएनएल
